SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, she is in the Lobby. Kindly ask the Marshal to call her here..... (Interuptions)....

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, they have been taken away by a special aircraft....(Interruptions) ....

MR. CHAIRMAN: I request Members not to raise irrelevant things. I have no right to confine Members, belonging to this side or that side. After coming in the House they are free to move out. I have no right. (Interruptions)

AN HON. MEMBER: I have given you the information. She is.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can give it afterwards. Don't waste the time of the House.

SHRI DIPEN GHOSH: If it were a wilful act, I would not have objected. But since she was made to leave the House.. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: According to me, it is my privilege to maintain discipline. And my ruling is that the question now raised is irrelevant. Kindly do not raise it. The Chair has no power to confine any Member within the precincts of the House. Please..(Interruptions) Question No. 284 Mr. Malaviya.

वाराणसी रामनगर-मुगलसराय को जोड़ने वाले गंगा के पुल का निर्माण

*284. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वाराणसी रामनगर-मुगलसराय को जोडने के लिए गंगा नदी पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) वाराणसी, रामनगर और मुगल सराय के बाहर से 30 कि०मी० लम्बी सड़क के साथ गंगा नदी पर एक पुल बनाने के लिए 49.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना संस्वीकृत की गई है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति महोदय, बनारस के आस-पास की जनता की यह मांग करीब-करीब 50 वर्षों से चली आ रही है और इससे 15 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से कम होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी, रामनगर और मुगलसराय को जोड़ने के लिए जो पुल बनाने की 50 करोड़ की योजना थी, इस पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कितने दिनों में पूरा होगा और कब तक यह पुल आवागमन के लिए खुलने की आशा है ?

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन साहब इस पुल की फाइनल रिपोर्ट 26 जुलाई, 1988 को स्टेट गवर्नमेंट के पास वेटिंग के लिए गई है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट आफ कम्पलीशन 1992 है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पुल की जो योजना है, क्या वह दो पार्टस में है यानी मेरा आशय यह है कि इस पुल में एक रास्ता आने के लिए और दूसरा जाने के लिए होगा ? क्या इस प्रकार की कोई योजना है ?

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन साहब, नक्शे में तो यह एक बाई-पास है और बनारस शहर और रामनगर, दोनों का बाई-पास से नदी पर पुल बनेगा ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह पुल जो वाराणसी, रामनगर और मुगलसराय को जोड़ने के लिए बन रहा है इसके निर्माण का

शिलान्यास कब हुआ था और किसने किया था ? क्या यह भी सही है कि इस योजना में लगभग 13 वर्षों का विलम्ब हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब जब इस योजना की स्वीकृति हुई है और राज्य सरकार को धन दिया गया है तो क्या राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि इस मामले में एकाउन्टेबिलिटी फिक्स की जाएगी ? यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जाएगा और कब तक जनता के उपयोग के लिए चालू कर दिया जाएगा ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, जैसे मैंने बताया है, यह अभी शुरू ही नहीं हुआ है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं बताना चाहूंगा कि इसका शिलान्यास श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1975 में किया था और उसके बाद लगभग 12 करोड़ की योजना बनी थी। गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण और अफसरों की मिली-भगत के कारण यह योजना अब 42 करोड़ तक पहुंच गई है और इस तरह से राष्ट्र के धन का दुरुपयोग हो रहा है। हर योजना के साथ इस तरह की चीज होती है और योजनाएं समय पर पूरी नहीं की जाती हैं । भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में इस पुल का शिलान्यास किया था, यह सूचना मैं आपको देना चाहता हूं...(व्यवधान) और 12 करोड़ रुपया...(व्यवधान)... चुनाव के समय नहीं हुआ, 1975 के समय कोई चुनाव नहीं था ।...(व्यवधान) लगभग 12-14 करोड़ रुपये की योजना उस समय बनाई गई थी और ठेकेदारी किसको मिले, क्या हो, इस रूप में वह लिगर करता रहा । कोर्ट में मामला चलता रहा ।

श्री सभापति : सवाल पूछिये । जानकारी लिखकर भेज दीजिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इतना विलम्ब क्यों हुआ और क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से आश्वासन लिया है एकाउन्टेबिलिटी उसकी फिक्स की है, कब तक यह पूरा हो जायेगा और जनता के उपयोग में आने लगेगा ।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य की पूरी इन्फर्मेशन सही नहीं है । जो मेरे विभाग की तरफ से मुझे इन्फर्मेशन मिली है वह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा । इसमें एक साल की देरी जरूर हुई है । जब इसका अवार्ड दे रहे थे टेंडर में तो हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का टेंडर वर्ल्ड बैंक ने क्लियर किया । लेकिन लोक सभा और राज्य सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने यह आग्रह किया कि इसे यू.पी. ब्रिज कारपोरेशन को देना चाहिये । 40-50 सदस्यों ने यह लिखकर दिया कि यह कांट्रेक्ट एच०सी०सी० के बजाय यू०पी० ब्रिज कारपोरेशन को देना चाहिये । इसके लिये फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया गया, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया गया । इसमें दो-तीन महीने लग गये । उसके बाद एक पार्टी कोर्ट में चली गई । इसमें एक साल का विलम्ब जरूर हुआ है । 27-2-87 को हम लोगों ने फाइनल टेंडर किया एच.सी.सी. के फेवर में । हम लोगों ने एम.पीज. की रेक्वेस्ट से इनिसियेटिव लिया और इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूछा, वर्ल्ड बैंक को पूछा । इसमें तीन महीने लग गये । जो गनानन इंडिया लि० है, जिसके सेकेंड लोएस्ट टेंडर थे वह कोर्ट में चला गया । इसमें इस तरह एक साल की देरी जरूर हुई । शिलान्यास के बारे में जो माननीय सदस्य बता रहे हैं वह मेरी जानकारी में नहीं है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : 12-14 करोड़ रुपये की योजना उसके लिये बनी थी । मंत्री महोदय यह बताने का भी कष्ट करें कि उनके मंत्रालय...

श्री सभापति : लिखकर दे दें, आपको उत्तर मिल जायेगा ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नदियों पर जो

बहुत से पुल बन रहे हैं जैसे कि गंगा नदी पर पटना में पुल बन रहा है जिसका उद्घाटन हो चुका है उस पर चार लेन का ब्रिज बनना है । दो लेन का उद्घाटन हो गया है और दो लेन पर काम चल रहा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ट्रैफिक स्ट्रक्चर दो लेन का हो या चार लेन का हो या छः लेन का हो तो अगर वह बनेगा तो वह एक साथ बनेगा या पार्टस में बनेगा ?

श्री राजेश पायलट : यह जो नेशनल हाई वे प्रोजेक्टस हैं ये नारमली दो लेन की शुरू में बनते हैं । चार लेन स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं । माननीय सदस्य जो पटना के बारे में कह रहे हैं उसकी जानकारी लेकर मैं उनको भेज दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि वर्ल्ड बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसके निर्माण में धन किस हिसाब से लगाया है । अगर इसके निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन को दे दिया गया है तो केन्द्रीय सरकार क्या इसके निर्माण का कार्य करेगी ?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, जैसा मैंने बताया यह यू० पी० ब्रिज कारपोरेशन को नहीं दिया गया है यह हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को दिया गया है क्योंकि यू०पी० ब्रिज कारपोरेशन इस टेंडर में कंपीट नहीं कर पाया, उसमें कुछ कमियां रही जिसे वर्ल्ड बैंक ने क्लियर नहीं किया । वर्ल्ड बैंक ने 27 मिलियन डालर दिए हैं जो सड़कों के लिये हैं । इसमें से 21 मिलियन डालर इस प्रोजेक्ट में यूज किया जायेगा । यह नेशनल हाई वे प्रोजेक्ट है और इसको केन्द्रीय सरकार एक्जीक्यूट करेगी यू० एच०सी०सी० जिसका टेंडर पास हुआ है । साथ ही इसमें पी०डब्ल्यू० डी० का भी हिस्सा काम में होगा । जो अप्रोच रोडस के काम हैं वे और लोगों को भी दिए हुए हैं ।

MR. CHAIRMAN: Now Mrs Suryakanta Patil.

SHRIMATI SURYAKANTA JAYAWANTRAO PATIL: No question. I am satisfied with the answer.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Spanish offer to supply CASA aircraft for Vayudoot

*283. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Spanish Prime Minister is reported to have announced at a press conference, jointly addressed by him and his Indian counterpart, that Spain would supply the CASA aircraft to the Vayudoot; if so, what are the details thereof;

(b) whether his Ministry is aware of the Spanish offer; if so, whether it meets Vayudoot's requirements; and

(c) whether Vayudoot had earlier dropped its consideration to purchase CASA aircraft and if so, what were the reasons therefor and what is Government's reaction to the present offer?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI MOTI LAL VORA): (a) The Spanish Prime Minister in the joint press conference while recounting the areas of economic inter-action between India and Spain also recalled and referred to the offer made for the supply of CASA 212 aircraft for sub-regional use.

(b) The terms offered for the lease/sale of CASA 212 aircraft were not found attractive by Vayudoot.

(c) The Evaluation Committee set up by Voyudoot to identify 40 plus seater Turbo-prop aircraft for induction in the fleet of Vayudoot considered among others CASA CN 235 air-